225 अरब डॉलर का मूल्य लगाया है विकिक विद्वान कावाकाज ट्रस्ट ने अंक्र क्र, लेकिन भारत का हिस्सा 10% से कम है, इसे बढ़ाना होगा

कैलाश विश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

उच्च शिक्षा

भारत में भी बढ़ेंगे विदेशी छात्र

भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की दिशा में यूजीसी निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 2022 में यूजीसी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालयों को विदेशी विद्यार्थियों के लिए वर्तमान सीटों में 25 प्रतिशत विस्तार करना था। परंतु अब तक इस दिशा में कम ही काम हो पाया है। संबंधित बुनियादी ढांचे में यदि पर्याप्त सुधार किया जाए, तो इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की जा सकती है

वह व्यवस्था विदेशी छात्रों को भारतीय संस्थानों से जोड़ेगी और उन्हें यहां की शिक्षा के प्रति आकर्षित करेगी। गौरतलब है कि 2016 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआइआरएफ) की शुरुआत हुई, जो भारतीय संस्थानों को वैश्विक प्रतिस्पर्धाक्षमता को बढ़ाती है। यह रैंकिंग विदेशी छात्रों को भारतीय संस्थानों की गुणवत्ता पर भरोसा दिलाएगी और उन्हें यहां आकर्षित करेगी। इसके पीछे...

भूमिकाएं : विदेशी छात्रों को भारत की शैक्षणिक भूमि पर आकर्षित करने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे कदम उठाने हैं, जिनमें समय रहते हटाना होगा। विदेशी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को लागत और पर्याप्त छात्रवृत्तियों का अभाव एक प्रमुख बाधा है। वित्तीय सहायता का अभाव विदेश रूप से शैक्षिक स्तरों और क्षेत्रों में भिन्न होता है, जो छात्रों को अन्य देशों की ओर आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, कुछ और कनाडा जैसे देश छात्रवृत्तियों और विशेष सहायता के साथ आकर्षक पैकेज प्रदान करते हैं, जिसमें भारत प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाता है। इसके अलावा, भारतीय विश्व की वैश्विक रैंकिंग और पहचान में कमी, अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा को कठिन बनाती है।

सुझाव : इन चुनौतियों को काबी जीवा प्रक्रियाएं छात्रों को हतोत्साहित करती हैं। ऐसे में भारत को जीवा प्रक्रियाओं को सरल और लैज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य देश जैसे आस्ट्रेलिया और कनाडा ने वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाकर छात्रों को आकर्षित किया है। विदेशी छात्रों के लिए विशेष वीजा श्रेणी बनाई जानी चाहिए, जिसमें अल्पावधान आवेदन और त्वरित स्वीकृति की सुविधा हो। उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचे को बेहतर भारत को अन्य देशों जैसे मलेशिया और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी जा सकती है।

आगे की राह : विदेशी छात्रों को बेहतर जीवनशैली और शैक्षिक अनुभव सुनिश्चित करने हेतु कैम्पस सुविधाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। साथ ही, सरकार को विदेशी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने चाहिए, जो उन्हीन फीस और रहने के खर्च को कवर करें। शिक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाकर और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके आधारभूत ढांचे पिकित रीवाप किए जा सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की भिन्न रैंकिंग गुणवत्ता के प्रति भरोसा बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में निवेश करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाना, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और विदेशी प्रोफेसरों को भारत में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा, शिक्षकों और छात्रों को वैश्विक मंचों पर भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इन सुझावों को लागू करने के साथ न केवल विदेशी छात्रों के लिए एक आकर्षक सेटिंग बन सकता है, बल्कि वैश्विक शिक्षा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ी सकता है। इसके लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जो नीतिगत सुधारों और संस्थागत सहयोग से संभव हो सकेगा।

वैश्विक मानकों के अनुरूप शैक्षिक व्यवस्था होने पर भारत में भी बड़ी संख्या में आ सकते हैं विदेशी छात्र। एआइ

विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन

गरिमा विष्वर्ट
लोक नीति विशेषज्ञा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने 2025 के दिशा-निर्देशों के तहत पहले बार भारत में विदेशी शैक्षणिक परिसरों को स्थापना की अनुमति दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय में अमेरिका के इलिनायस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी और आस्ट्रेलिया की वोलोंगांग यूनिवर्सिटी सहित कुल पांच प्रस्ताव विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है, जो 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से भारत में अपने कैंपस शुरू करने की योजना बना रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए क्यों से विदेश को रुख पकड़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों के लिए यह खत्म की खबर साबित होगी, क्योंकि अब वे वैश्विक गुणवत्ता की शिक्षण सुविधाएं अपनी मातृभूमि की सीमाओं के भीतर ही पा सकेंगे।

भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य में एक नया अध्याय तब जुड़ा, जब पूर्वमें 2023 में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी। यह निर्णय केवल एक स्थापित नियम नहीं था, बल्कि शिक्षा के वैश्विक मानचित्र पर भारत की स्थिति को मजबूती से स्थापित करने का साहस इकट्ठा दर्शाता है। यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों के तहत केवल वैश्विक शीर्ष 500 में शामिल इन विश्वविद्यालयों को ही भारत में शाखा खोलने की पात्रता मिली, जिसमें इस पहल की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। इन विश्वविद्यालयों को संस्थागत स्वायत्तता का पूर्ण अधिकार दिया गया है, यानी वे प्रवेश नीति, शुल्क संरचना और पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी निर्णय अपने विवेक से ले सकेंगे। इससे वे अपने बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार कर सकेंगे।

इस निर्णय के पीछे भारत की एक स्लोबल शिक्षा हब बनाने का लक्ष्य निहित है। इस पहल से विद्यार्थियों को स्थानीय परिसरों में ही अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक माहौल का अनुभव मिलेगा, जहां भारतीय और विदेशी दोनों छात्र एक ही छात्र मिल-जुलकर अध्ययन करेंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत आने से हमारे शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध होगी, तो भारतीय विश्वविद्यालय भी अपनी पाठ्यक्रम संरचना, शिक्षण पद्धतियों और शोध गतिविधियों को मजबूत करने के लिए प्रेरित होंगे। परिणामस्वरूप संपूर्ण शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा, जिससे समग्र शिक्षण-शिक्षण अनुभव ही नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर भी व्यापक होंगे।

इस पहल का अधिक लाभ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश प्रवाह से भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। नए परिसरों के निर्माण, संकाय नियुक्ति, समग्री खरीदारी और स्थानीय सेवाओं के लिए बड़ी से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी तरह विदेशी छात्रों के आगमन से आवास, भोजन, परिवहन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी अर्थव्यवस्था को भी भरपूर प्रोत्साहन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भारत का शिक्षा बाजार 2025 में 225 अरब डालर तक पहुंचने की संभावना है, जो वैश्विक शिक्षा बाजार के 7.6 लाख करोड़ डालर के बाजार की तुलना में केवल तीन प्रतिशत हिस्सा ही है।

वहीं दूसरी ओर, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने से शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होगा। विदेशी निवेश और स्वायत्त रूप से शुल्क निर्धारण जैसे अर्थव्यवस्था की विकसा और मजबूती प्रदान करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम और शोध गतिविधियां नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग प्रसारों के नए द्वार खोलेंगी। इससे भारतीय शिक्षा को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती मिलेगी। इस पहल के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। यह निर्णय केवल एक स्थापित नियम नहीं था, बल्कि शिक्षा के वैश्विक मानचित्र पर भारत की स्थिति को मजबूती से स्थापित करने का साहस इकट्ठा दर्शाता है। यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों के तहत केवल वैश्विक शीर्ष 500 में शामिल इन विश्वविद्यालयों को ही भारत में शाखा खोलने की पात्रता मिली, जिससे इस पहल की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। इन विश्वविद्यालयों को संस्थागत स्वायत्तता का पूर्ण अधिकार दिया गया है, यानी वे प्रवेश नीति, शुल्क संरचना और पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी निर्णय अपने विवेक से ले सकेंगे। इससे वे अपने बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार कर सकेंगे।

इस निर्णय के पीछे भारत को एक स्लोबल शिक्षा हब बनाने का लक्ष्य निहित है। इस पहल से विद्यार्थियों को स्थानीय परिसरों में ही अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक माहौल का अनुभव मिलेगा, जहां भारतीय और विदेशी दोनों छात्र एक ही छात्र मिल-जुलकर अध्ययन करेंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत आने से हमारे शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध होगी, तो भारतीय विश्वविद्यालय भी अपनी पाठ्यक्रम संरचना, शिक्षण पद्धतियों और शोध गतिविधियों को मजबूत करने के लिए प्रेरित होंगे। परिणामस्वरूप संपूर्ण शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा, जिससे समग्र शिक्षण-शिक्षण अनुभव ही नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर भी व्यापक होंगे।

इस पहल का अधिक लाभ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश प्रवाह से भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। नए परिसरों के निर्माण, संकाय नियुक्ति, समग्री खरीदारी और स्थानीय सेवाओं के लिए बड़ी से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी तरह विदेशी छात्रों के आगमन से आवास, भोजन, परिवहन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी अर्थव्यवस्था को भी भरपूर प्रोत्साहन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भारत का शिक्षा बाजार 2025 में 225 अरब डालर तक पहुंचने की संभावना है, जो वैश्विक शिक्षा बाजार के 7.6 लाख करोड़ डालर के बाजार की तुलना में केवल तीन प्रतिशत हिस्सा ही है।

वहीं दूसरी ओर, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने से शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होगा। विदेशी निवेश और स्वायत्त रूप से शुल्क निर्धारण जैसे अर्थव्यवस्था की विकसा और मजबूती प्रदान करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम और शोध गतिविधियां नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग प्रसारों के नए द्वार खोलेंगी और तकनीकी प्रगति को गति मिलेगी, जिससे न केवल शिक्षा, बल्कि उद्योग जगत को भी लाभ होगा। वहीं, छात्रों को विदेशी संस्कृतियों, भाषाओं और विचारधाराओं का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, जो उनके व्यक्तित्व विकास और वैश्विक दृष्टिकोण को सशक्त बनाएगा।

खरी-खरी

अंधेर नगरी और चौपट राजा

हूल सरमा

कटौती किए जाने के कारण लंबे समय से उस नगर की बिजली नहीं आ रही थी। अंधेरे के जंगल में अंधेरे का फायदा उठाकर अपने कारनामों को अंजाम दे रहे थे। चोर, उचक्के और बदमाश अपनी-अपनी करामतों में ग्रस्त हो गए थे। उस नगरी का राजा भी गहरे नींद में सो गया था और बगल कोठालल, तो उसकी आंखों में भला नींद कहां? वह भी अंधेरे के कारण से नहीं पर यह था, चोर, उचक्के और बदमाश सक्रिय हो तो उसकी आंखें नींद कैसे ले सकती थीं? वह सबकी खबर लेकर अपनी जेब गर्म कर रहा था। गलती से भी उस ओर उसे अंधेर नगरी में। किसी ने मेरे उसर दाबी का उजाला कर दिया। अब कहां जाओ। कौन हो तुम? मैंने मतवाता पहचान पत्र निकाला और बोला- "मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक मुसाई लाल हूं। इस बार उसने पूछा- 'जानते हो, मैं कौन हूं।' मैंने कहा- 'नहीं सर, मैं शहर में नया हूं। आपको नहीं पहचानता। आप अपना परिचय दीजिए। आपका परिचय पाकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी।' मैंने अंधेरे में उसे गौर से देखा, वही मूंछें मैं अपने उसका पेहेर पैबंदवाला शाल मेरे दंडा था। वह बड़े शैख से बोला- 'मुझे पहचानो, मैं इस शहर का कोतवाल, घसेरीराम कोतवाल हूं।'

मैंने कहा- 'जय हो जनाब- पहचान लगते ही। लेकिन सर आप इस रात में कहां भटक रहे हैं?' घसेरीराम कोतवाल बोला- 'मैं मुसाई लाल को तलाश रहा हूं। मेरा भाई वह मिल गया। मैं भटक नहीं रहा मूर्ख, मैं शहर की रहा में आंखों को नींद उड़ कर मालगुजार मिल गया। मैंने राज-काज संभाल रहा हूं।' मैं हर गया- 'सर, मैं वहीं ठहरने के लिए किसी धर्मशाला की तलाश में हूं।' कोतवाल हंसकर बोला- 'तुम चले आए यहां। तुम इस अंधेरे रात में निकले कहां से हो?' मैं बोला- 'सर, मैं तो पास के गांव से आया था। अतो-आतो रात हो गई।' एक सज्जन और इमानदार आदमी हूं। आप मुझे पर शक कर रहे हैं।'

तब तक पुलिस वाले, हम शक के आधार पर अपराधी तक पहुंचेंगे हैं, पूनो आने तुम्हारा मतवाता पहचान पत्र मुझे नहीं, 'चौपट सिंह महाराज के खानत।'

पोस्ट

जाइन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना पर जेनी वेलो की प्रति व्यक्ति आय का हवाला देने वाले लोग इसे अनदेखा क्यों कर देते हैं कि लाख लाभान्वित जी डीबी 0.6 प्रतिशत से बढ़ कर 1.4 हो गई थाई भारत की जी डीबी लगातार छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज कर रही है।

मिहाता मर्टे@MinhazMerchant

ब्राजील में गुलतुल पलाना वाले ब्राजीली नागरिक जोनास मेरोट्टो को पुरुषार्थ मिलता

देखकर बहुत खुशी हुई। एक समय दुर्जन और परवर्ती लोगों तक सीमित रहे हमारे ने पुरस्कार आज सुयोग्य को मिलने लगे हैं। इस मोर्चे पर भी देश ने बड़ी उन्नति हासल लगाई है।

मनीका वर्मा@TrulyMonica

तो इस की सीजाबयार शाली नोटों और उसके लिए सिंक्रेट डाल का लाभ भारत-पाकिस्तान को देने की सहमती अमेरिकी कांग्रेट की अमा-सन्नाट डिलीज के फैसलों पर वत रहे केस के लिए नयी गई थी। यह तहलमी भी अमेरिकी कोर्ट में खारिज कर दी।

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

झारखंड

डायरी

प्रति रोकर
संवाददाता जमशेदपुर, रांची

झारखंड तक पहुंची शराब घोटाले की आंच

राजस्व की क्षति पहुंचाने का आरोप। प्रतीकात्मक

शराब घोटाले को लेकर झारखंड एक बार फिर से चर्चा में है। इससे पहले झारखंड में अवैध खनन घोटाले और जमीन घोटाले की ईडी जांच के दौरान राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक की गिरफ्तारी का मामला सुर्खियों में रह चुका है। झारखंड के शराब घोटाले में भी अब ईडी और सीबीआइ की जांच की आंच इसीलिए से होते हुए घेरे-घेरे यहां तक पहुंच रही है।

गौरतलब है राज्य सरकार की एसीबी एसीबी ही इस मामले में पूरे एकमात्र में है। राज्य के पूर्व उत्पाद सचिव, उत्पाद विभाग (आबकारी विभाग) के महत्वाकांक्षा, पूर्व महत्वाकांक्षा समेत चांच लोग अब तक इस मामले में एसीबी के कार्य गिरफ्तार हो चुके हैं और गिरफ्तार होने वाले अधिकारी नौके के परमार्थी थे। शराब के एक साथ सिंडिकेट को पहचान भी इसीलिए ही हो सकी है, जिसमें कमीशन अफसरों की जेब में पहुंचा, लेकिन सरकारी राजस्व को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी? इसी सवाल पर शराब के एक साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी जा सकती है।

आगे की राह : विदेशी छात्रों को बेहतर जीवनशैली और शैक्षिक अनुभव सुनिश्चित करने हेतु कैम्पस सुविधाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। साथ ही, सरकार को विदेशी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने चाहिए, जो उन्हीन फीस और रहने के खर्च को कवर करें। शिक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाकर और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके आधारभूत ढांचे पिकित रीवाप किए जा सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की भिन्न रैंकिंग गुणवत्ता के प्रति भरोसा बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में निवेश करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाना, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और विदेशी प्रोफेसरों को भारत में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा, शिक्षकों और छात्रों को वैश्विक मंचों पर भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इन सुझावों को लागू करने के साथ न केवल विदेशी छात्रों के लिए एक आकर्षक सेटिंग बन सकता है, बल्कि वैश्विक शिक्षा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ी सकता है। इसके लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जो नीतिगत सुधारों और संस्थागत सहयोग से संभव हो सकेगा।

पवर सरनाई एजेंसियों के निर्देशों और अफसरों के कारोबारी संपत्ति ट्रस्टनेवर लौगें की एसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। समन में 15 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की जांच पर हैरान है, लेकिन स्वयं एसीबी भी मान रही है कि यह घोटाला 100 करोड़ रुपये से ऊपर का है। वहीं दूसरी ओर, प्रदेश में विपक्षी दल भाजपा जनता पार्टी ने इसे दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला बताया है। भाजपा इसी कारण सीबीआइ जांच की आवश्यक बता रही है।

शराब के कारण दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में पहले तो भूचाल आ चुका है। अब इसियगढ़ के बाद झारखंड में शराब घोटाले का जिन्न सामने आया है। यहां के शराब घोटाले को पटरका भी छत्तीसगढ़ में ही लिखी गई थी। यहां भी शराब की बिक्री में छत्तीसगढ़ का ही घाटता अपनाया गया। उदाहरण छत्तीसगढ़ के अधिकारी ही के हो गए। यहां पहले तो शराब की बिक्री एजेंसियों की पूछी कई गई, जिसमें कमीशन अफसरों की जेब में पहुंचा, लेकिन सरकारी राजस्व को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी? इसी सवाल पर शराब के एक साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी जा सकती है।

आगे की राह : विदेशी छात्रों को बेहतर जीवनशैली और शैक्षिक अनुभव सुनिश्चित करने हेतु कैम्पस सुविधाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। साथ ही, सरकार को विदेशी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने चाहिए, जो उन्हीन फीस और रहने के खर्च को कवर करें। शिक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाकर और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके आधारभूत ढांचे पिकित रीवाप किए जा सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की भिन्न रैंकिंग गुणवत्ता के प्रति भरोसा बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में निवेश करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाना, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और विदेशी प्रोफेसरों को भारत में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा, शिक्षकों और छात्रों को वैश्विक मंचों पर भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इन सुझावों को लागू करने के साथ न केवल विदेशी छात्रों के लिए एक आकर्षक सेटिंग बन सकता है, बल्कि वैश्विक शिक्षा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ी सकता है। इसके लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जो नीतिगत सुधारों और संस्थागत सहयोग से संभव हो सकेगा।

स्मरण

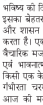

ड. गुंजन रजपूत
रीसर्चर, कांकुइस विवि, सोनीपत, हरियाणा

कुशल एवं मजबूत प्रशासक अहिल्याबाई

कल राजी अहल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है। देश के सामजिक एवं आर्थिक उत्थान में उनका व्यापक योगदान रहा है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने तीन सौ वर्ष पहले थे। उनके निर्णय समय से आगे के प्रतीत होते हैं

किसी भी देश की मजबूती वहां के सुदृढ़ व्यवस्था के निर्माण से होती है जिसमें उस राष्ट्र उसके निर्माण भविष्य की दिशा एवं दशा तय करती है। इसका बेहतर होना एक अच्छे शासक और शासन पर बहुत हद तक निर्भर करता है। एक शासक में मानसिक एवं वैचारिक मजबूती, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता एवं भावनात्मकता होना अनिवार्य है। किसी एक के भी अभाव में निर्णयों की गंभीरता घटकर जाती है। भारत की आज की मजबूती के पीछे आज का शासन प्रशासनात्मक एवं उसकी मजबूत नीतियां हैं, यही भारत जिस हित से पर, धर्म की राह पर चलने वाले, उन एवं राष्ट्र सेवक जैसे आदर्शवादी शासकों की सोतानें की धूमि रहा है जिसका एक उदाहरण थीं- अहिल्याबाई होलकर।

"न्याय का नाम लेकर मैं जिस पर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है"- इस कथन से उनका राष्ट्र निर्माण के प्रति समग्रता धलीधति समझा जा सकता है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय अपने समय से बहुत आगे के सोच को दर्शाते हैं। ग्रमीण पृष्ठभूमि वाले सामान्य परिवार की बालिका से एक अत्यन्त प्रसाक तक की उनकी जीवनयात्रा आसान नहीं थी या कह सकते हैं कि जटिलताओं से भरी थी। भारत की आज जहां महिलाओं के पिछड़ेपन के लिए विश्वसर पर व्यवस्थाएं होने के जो आज के संदर्भ में न केवल महिलाओं, बल्कि हर शख्स के लिए एक सोच है उन आज के संदर्भ में बुरा है। यह कथन का विचलित होने पर उनके निर्णय की क्षमता को प्रभावित करता है। परंतु निजी जीवन में संकट्ठठ खो देने के बाद भी अहिल्याबाई एक निडर योद्धा की तरह आत्म तलहारी रहीं। जहां आज काम में एकाग्रता के लिए लोग परिवार को अमनियत नहीं दे पाते, वहां परिवार, उसकी जिम्मेदारियों, उसके दुख-सुखों के साथ समाज के लिए सही नियोपक बनना अहिल्याबाई से सीखना है।

महारानी अहिल्याबाई होलकर।

अहिल्याबाई ने परिवारवाद के कभी बढ़ावा भी नहीं दिया जिसे उनके अपने ही एक वंशीय में लिए गए कई निर्णयों के संबंध में देखा जा सकता है। अच्छे शासन की कला विरासत में मिले यह उनके हाथ आए अनगिनत अवसरों में है यह भी आवश्यक नहीं। बार बार उस योग्य को मिलनी चाहिए जिसके गुण एक शासक में होना चाहिए, जो कि किसी भी शासक को अहिल्याबाई के सेक्ष कभी को याद में रखना चाहिए, चाहे वह सही अर्थ में शासन, चाहे मंत्रिमंडल की मंत्रिमंडल, चाहे मंत्रिमंडल की शख्स विधा, चाहे परिवार के लिए त्याग, चाहे स्टीक युद्ध नीति हो।

****